जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 33 संख्याः 109 प्रभात अजमेर, शनिवार, 22 नवम्बर, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

क्या मजबूरी है राहुल गांधी की: वादा करते हैं, पर निभा नहीं पाते?

राहुल गांधी के वादे के अनुसार, कर्नाटक में ''रोटेशन'' से ढाई साल बाद, मु.मंत्री बदलना चाहिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। ढाई साल पहले राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि कर्नाटक में पहले ढाई साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले ढाई साल डी. के. शिवकुमार। यह परिवर्तन नवंबर 2025 में होना था।

लेकिन नवंबर आते ही राहुल गांधी की ओर से पूरी तरह चुप्पी छाई हुई है, जबकि डी. के. शिवकुमार बेचैनी की हालत में अपने विधायकों को लॉबिइंग करने भेज रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि वे पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने की हरी झंडी मिल गई है, जिसका मतलब है कि वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधानसभा सत्र 8 दिसंबर

- **ये ढाई साल नवम्बर 2025 में पूरे हो गये, पर, ''रोटेशन'' की कोई चर्चा ही नहीं हो रही।**
- **डी.के. शिवकुमार, अपनी बारी का इन्तज़ार कर रहे हैं, पर, मु.मंत्री सिद्धारमैया, मंत्रिमण्डल में फेर-बदल की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा सत्र, आठ दिसम्बर को शुरु होने से पहले।**
- **मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेवारी सौंपी गई है, इस झमेले को सुलझाने की।**
- **पर, सवाल यह उठ रहा है, राहुल गांधी ऐसे वादे ही क्यों करते हैं, जिनसे झमेले उत्पन्न हों तथा सुलझाने की गंभीर जरुरत हो।**
- **गम्भीरता की बात इसलिए उठ रही है, क्योंकि निराश डी.के. शिवकुमार भाजपा की ओर न मुड़ जाएं।**

से शुरू हो रहा है और उससे पहले ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद है।

डी. के. शिवकुमार अस्पष्ट से बयान दे रहे हैं–कि सभी 140 विधायक उनके हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, और यह कि सिद्धारमैया ने कहा है कि वे 5 साल तक रहेंगे, तो उन्हें शुभकामनाएं।

शिवकुमार के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, कर्नाटक की इस उलझन को सुलझाने के लिए जो भी शर्तें या समझौते करने होंगे, वह सब खड़गे के स्तर पर ही तय किया जाएगा।

पार्टी में यह डर भी है कि डी. के. शिवकुमार कहीं भाजपा में न चले जाएं।

साथ ही, इस बात को लेकर भी चिंता है कि राहुल गांधी मनमाने तरीके से वादे कर देते हैं लेकिन फिर उन्हें निभाते नहीं। ऐसा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हुआ, जहाँ पार्टी दो हिस्सों में बंटी और हालात बिगड़ते गए–जिन्हें राहुल हल नहीं कर पाए।

दरभंगा -दिल्ली स्पाइसजेट उड़ान में बम की सूचना

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। बिहार के दरभंगा से दिल्ली आ रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में बम होने की चेतावनी के बाद, यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को विमान और सभी यात्रियों की गहन जांच की जा रही है।

उड़ान संख्या एसजी 752 ने आज दोपहर बाद 2:55 बजे दरभंगा से उड़ान

- **पूरी सुरक्षा के साथ विमान की दिल्ली में सकुशल लैंडिंग हुई।**

भरी थी और शाम 4:46 बजे दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल–3 पर उतरी।

सूत्रों ने बताया कि विमान की लैंडिंग से कुछ देर पहले ही किसी ने हवाई अड्डे के कॉल सेंटर पर फोन करके विमान में बम होने की सूचना दी थी। इसकी सूचना तुरन्त सुरक्षा एजेंसियों और नियामकों को दी गयी। इसके बाद पूरी सुरक्षा के बीच विमान को टर्मिनल–3 पर सुरक्षित उतारा गया। विमान और सभी यात्रियों की जांच अभी जारी है।

इसी उड़ान में दरभंगा से दिल्ली आये एक यात्री ने बताया कि लैंडिंग के बाद करीब डेढ़ घंटे तक यात्रियों को विमान से नहीं उतारा गया। इसके बाद एक–एक यात्री की जांच कर उन्हें उतारने की प्रक्रिया शुरू की गयी।

उल्लेखनीय है कि गत 12 नवंबर को दिल्ली समेत देश के पांच हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मंत्रिमण्डल के गठन में नीतीश कुमार दबते नज़र आ रहे हैं

पहले तो नीतीश को विधानसभाध्यक्ष पद के मुद्दे पर, भाजपा की माननी पड़ी

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। बदलती राजनीतिक शक्ति–संतुलन का संकेत देते हुए, मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आज गृह विभाग पर अपना दावा छोड़ दिया और यह विभाग उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सम्राट चौधरी को दे दिया।

गृह विभाग पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहता था और विभागों के बंटवारे को लेकर हुई बातचीत में जेडीयू ने इस विभाग पर अपना मजबूत दावा जताया था। मुख्यमंत्री कुमार का इस मुद्दे पर नरम पड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले वे भाजपा की यह माँग मान चुके हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भाजपा का प्रतिनिधि ही रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता और नौ बार के विधायक प्रेम कुमार का नाम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विचाराधीन बताया जा रहा है।

सम्राट चौधरी को गृह मन्त्रालय की जिम्मेदारी देना भी महत्वपूर्ण माना जा

- **और, अब गृह मंत्री के मसले पर भी भाजपा ने पुनः अपनी बात मनवा ली और भाजपा नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्री नियुक्त करवाया। हालाँकि, यह विभाग हमेशा से बिहार में मु.मंत्री के पास ही रहता आया है।**
- **सम्राट चौधरी का गृह मंत्री बनना इसलिए और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर शुरु से ही चौधरी पर भ्रष्टाचार में लिप्त व हत्याकांड में फंसे होने का आरोप लगाकर उनका विरोध करते रहे हैं और अपना अभियान आगे चालू रखने की धमकी दे रखी है।**
- **भाजपा ने प्रशांत किशोर की धमकी को अंगूठा दिखाते हुए, अपने नेता सम्राट चौधरी को ही गृह मंत्री बनवाया।**

रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि जेएसपी नेता प्रशांत किशोर लगातार उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, और हत्या के एक केस में उनके आरोपी होने जैसे मुद्दों को लेकर चौधरी को निशाना बना रहे हैं। सम्राट के पक्ष में खड़े होकर और उन्हें गृह विभाग जैसे मुख्य मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर भाजपा नेतृत्व जाहिर तौर पर अपने विरोधियों और आलोचकों को चुनौती देना चाहता है।

लेकिन प्रशांत किशोर ने आज कहा कि ''राज्य मंत्रिमंडल में भ्रष्ट और अपराधी मंत्रियों'' के खिलाफ उनका अभियान बिना रुके जारी रहेगा।

भाजपा को इस बार कई महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। भाजपा विधायक दल के उपनेता विजय कुमार सिन्हा को राजस्व और भूमि सुधार विभाग मिला है; मंगल पांडेय के पास स्वास्थ्य विभाग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अखिल अरोड़ा अतिरिक्त मुख्य सचिव सी.एम.ओ. बने

शिखर अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, एम.एस.एम.ई. तथा रीको चेयरमैन के पद पर लगाया

जयपुर (कासं), 21 नवंबर। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी अखिल अरोड़ा को अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान के पद पर लगाया है। उनके पास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार यथावत् रहेगा।

इसी प्रकार शिखर अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव; उद्योग, एम.एस.एम.ई, राजकीय उपक्रम, दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, रीको अध्यक्ष, राजसीको अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिखर अग्रवाल के पास ही विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय एवं निवेश संवर्द्धन ब्यूरो के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद का कार्यभार होगा।

राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर 48 आई.ए.एस.

- **अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन, कला-संस्कृति, आमेर विकास प्राधिकरण और जवाहर कला केन्द्र की जिम्मेदारी मिली।**

अधिकारियों का तबादला किया। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रमुख शासन सचिव स्तर से लेकर कई संभागीय आयुक्त और वर्ष 2018 बैच तक के अफसरों का तबादला किया गया।

आदेश के अनुसार, प्रवीण गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन, कला–संस्कृति तथा महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र जयपुर के पद पर लगाया है। गुप्ता को राजस्थान पर्यटन विकास विकास निगम के अध्यक्ष तथा आमेर विकास प्राधिकरण जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है।

इसी प्रकार आलोक गुप्ता को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर के अध्यक्ष, दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर के पद पर लगाया है।

इसके अलावा, राजेश कुमार यादव को महानिदेशक, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर, गायत्री ए. राठौड़ को प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायती राज (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रक्षा मंत्री ने तेजस विमान पायलट की मौत पर दुख व्यक्त किया

नयी दिल्ली, 21 नवम्बर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई एयर शो में भारतीय वायु सेना के एक तेजस विमान की दुर्घटना में पायलट की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है।

सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा ,'' दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन

- **राजनाथ सिंह ने कहा कि दुबई एयर शो में भारतीय वायु सेना के बहादुर साहसी पायलट की मौत पूरा देश दुखी है।**

के दौरान वायु सेना के एक बहादुर और साहसी पायलट के जाने से बहुत दुख हुआ। दुखी परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।''

उल्लेखनीय है कि तेजस विमान दुबई एयर शो में शुक्रवार को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश हुआ, पायलट की मौत

तेजस विमान के 23 साल के इतिहास में दूसरी बार यह हादसा हुआ है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवंबर। देश की विमानन छवि को लगे एक बड़े धक्के के अन्तर्गत, शुक्रवार दोपहर दुबई एयर शो में उड़ान प्रदर्शन के दौरान एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक सामान्य प्रदर्शन एक चिंताजनक पल में बदल गया। विमान काले धुएं के घने गुबार के साथ अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिर गया, जिससे इसके पायलट की जान चली गई।

यह दो साल के अन्दर हुई तेजस विमान की दूसरी दुर्घटना है। मार्च 2024 में, एक तेजस विमान राजस्थान के जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह इसके 23 साल के इतिहास में पहली दुर्घटना थी, जो 2001 में इसकी पहली परीक्षण उड़ान के बाद हुई थी। उस दुर्घटना में पायलट बाल–बाल बचा था।

प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियोज़ के

- **वर्ष 2001 में तेजस विमान की पहली टैस्ट फ्लाइट हुई थी और मार्च 2024 में जैसलमेर में पहली बार तेजस विमान क्रैश हुआ था।**
- **यह सिंगल सीटर हल्का लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इस हादसे से देश की ''एविएशन इमेज'' को झटका लगा है।**
- **दुबई एयर शो का आयोजन अल मकतूम इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर हुआ था और स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:10 पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।**

अनुसार, यह विमान, जिसे सिंगल–सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने विकसित किया है, स्थानीय समयानुसार करीब 2:10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

भारतीय वायु सेना ने ''एक्स'' पर पोस्ट किया, ''आज दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक आईएएफ तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भारतीय वायु सेना पायलट की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के साथ इस कठिन समय में मजबूती से खड़ी है। एक जांच समिति बनाई जा रही है, ताकि दुर्घटना का कारण पता लगाया जा सके।'' इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ़ हेडक्वार्टर ने ''एक्स'' पर पोस्ट किया, ''जनरल अनिल चौहान, सीडीएस और भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंक इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं, जिसमें आज दुबई एयर शो में एक आईएएफ तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम पायलट की जीवन–हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के साथ इस कठिन समय में मजबूती से खड़े हैं।

एयर शो में मौजूद दर्शकों ने देखा कि विमान रूटीन प्रदर्शन के दौरान ऊंचाई से नीचे की ओर आने लगा। कुछ ही सेकंडों में, यह रनवे की इमारतों के पीछे गायब हो गया और एक काले धुएं का गुबार उठते हुए दिखा, जिससे दर्शकों और कर्मचारियों के बीच घबराहट फैल गई। जहां मोदी सरकार रक्षा प्रणालियों और वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं, प्रतिष्ठित दुबई एयर शो में इस दुर्घटना का होना इस प्रयास के लिए एक बड़ा झटका है।

केरल व यूपी में एसआईआर को चुनौती

नई दिल्ली, 22 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल, यूपी समेत अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति

- **सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा।**

जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में लोकल बॉडी के चुनाव भी होने हैं और इसलिए, इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप का 28 सूत्रीय ''प्लान'' सार्वजनिक किया गया

आम राय है कि इस ''प्लान'' को रूस की सहमति तो मिल जाएगी, पर, यूक्रेन के लम्बे युद्ध के बाद, इस प्लान को यूक्रेन की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका की यूक्रेन–रूस युद्ध समाप्ति की 28 सूत्रीय योजना के प्रारूप के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद, यूरोप और कीव के कूटनीतिज्ञों में यही सवाल उठ रहा है: क्या यह योजना व्यावहारिक है, और क्या इस पर दोनों संघर्षरत पक्षों की सहमति प्राप्त की जा सकती है?

पहली नज़र में, यह प्रारूप, जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की के साथ साझा किया गया था और, रिपोर्ट्स के अनुसार, मॉस्को के साथ इस पर गुप्त चर्चा की गई थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। इसमें स्थायी युद्धिवराम, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी, रूस, यूरोप और कीव के बीच एक गैर–आक्रमण संधि, और फ्रीज की हुई रूसी संपत्तियों से आंशिक रूप से वित्त पोषित एक बड़ी पुनर्निर्माण योजना का वादा किया गया है। इसमें रूस और पश्चिम के बीच आर्थिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने का मार्ग भी दिया गया है और प्रस्तावित है कि अमेरिकी राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से एक ''शांति परिषद'' का नेतृत्व करेंगे, जो इसे लागू करने का कार्य करेगी। लेकिन इस प्रस्ताव का विस्तार ही इसके विरोधाभासों का कारण भी है, और आलोचकों के अनुसार, यह खतरनाक है।

प्रारूप के सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए तत्वों से संकेत मिलता है कि

- **14-रूस को प्लान माफिक तो आएगा, पर, रूस इस प्लान के तहत किए गए वादों को निभाएगा ही, इसकी गारंटी कौन ले सकता है।**
- **यूरोपीय देशों का मानना है, इस ''समझौते'' से ''संकट'' केवल कुछ समय के लिए आगे खिसक जाएगा, दोबारा विकराल रूप अपनाने से पहले। क्योंकि थका हारा, यूक्रेन बेमन से ही, इस ''समझौते'' को अपनाएगा, क्योंकि इस समझौते के बाद, यूक्रेन एक ''बफर राज्य'' बनकर रह जाएगा, स्वतंत्र व बराबर के स्टेटस का देश नहीं रहेगा।**

यूक्रेन को कई महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को स्वीकार करना होगा। कीव को औपचारिक एवं कानूनी घोषणा करनी पड़ेगी कि वह भविष्य में नाटो की सदस्यता नहीं लेगा, अपनी सेना के आकार को लगभग 600,000 कर्मियों तक सीमित रखेगा और लंबी दूरी तक मार करने वाले उन हथियारों पर प्रतिबंध स्वीकार करेगा, जो रूस के भीतर हमला कर सकते हैं। इसकी भूमि पर नाटो सैनिकों को तैनात नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान में पदस्थ लोगों को ये शर्तें सही नहीं लग रही हैं। उन्हें लगता है कि ये शर्तें उनके देश की सैन्य और विदेश नीति संबंधी मामलों में स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता छीन लेंगी, जबकि यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए रूस से युद्ध लड़ा और भारी कीमत चुकाई।

ज़ेलेन्स्की ने दस्तावेज़ को सीधे खारिज करने का विकल्प नहीं चुना है; उन्होंने कहा है कि वे अमेरिकी प्रशासन के साथ ''योजना पर काम करने'' के लिए तैयार हैं। लेकिन कीव से प्रतिक्रियाएँ काफ़ी संदेहास्पद रही हैं। कुछ सलाहकारों ने मुख्य प्रावधानों को ''बेतुका'' बताया है, चेतावनी दी है कि कोई भी ऐसा समझौता, जो क्षेत्रीय दावों या रणनीतिक स्वायत्तता को त्यागता है, युद्ध से जूझ रही आबादी को स्वीकार्य नहीं हो सकता।

रूस, इस बीच, केवल सतर्क रूप से सहमति दिखा रहा है। जबकि कई शर्तें रूस के पक्ष में हैं, यूक्रेन की सेना पर प्रतिबंध, नाटो की महत्वाकांक्षाओं को स्थगित करना और प्रतिबंधों में राहत की संभावना। फिर भी मॉस्को में अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि प्रारूप उन ''मूल कारणों'' का समाधान नहीं करता, जिन्हें वे युद्ध का कारण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आखिरी कार्य दिवस पर भावुक हुए सीजेआई गवई

नई दिल्ली, 22 नवंबर। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई ने शुक्रवार को कहा कि वे लगभग चार दशक लंबे अपने कानूनी और न्यायिक सफर के अंत में पूरे संतोष और तृप्ति के साथ न्याय के छात्र के तौर पर इस संस्था

- **सीजेआई ने कहा देश के लिए जो कर सकता था किया, इसी संतुष्टि के साथ जा रहा हूँ।**

को छोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि सीजेआई गवई का सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दिन था। वे इस दौरान विदाई समारोह के लिए गठित बेंच के साथ कार्यवाही पर बैठते हुए भावुक नजर आए। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनोद चंद्रन मौजूद थे।

सीजेआई गवई ने कहा, आप सभी को सुनने के बाद, खासकर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और कपिल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)